भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 213
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण,1947 (शक) को दिया जाना है)

महंगाई और बेरोज़गारी

213 श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोज़गारी और महंगाई की मौजूदा प्रवृत्ति और कारण क्या हैं और वे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं;

(ख) सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौन-सी नीतियाँ और नियामक तंत्र निर्धारित किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किये गए इन हस्तक्षेपों से कीमतों में स्थिरता लाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के बीच संतुलन बनाने में किस प्रकार मदद मिली है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 (जुलाई से जून अवधि) के अनुसार, 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आखिल भारतीय वार्षिक बेरोज़गारी दर (सामान्य स्थिति के अनुसार) 2017-18 के 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई। वहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फिति दर (वर्ष दर वर्ष) 2023-24 के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.6 प्रतिशत हो गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। यह 2025-26 (अप्रैल-अक्टूबर) में और कम हुई, और औसत खुदरा मुद्रस्फिति कम होकर 1.9 प्रतिशत हो गई।

आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, उच्च बेरोज़गारी की अवधि में वेतन दबाव कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू मांग में कमी आ सकती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फिति दबाव कम हो सकता है। तथापि, भारत के संदर्भ में, बेरोज़गारी और मुद्रास्फिति दर के बीच का संबंध कई वजहों से तय होता है, जैसे कि श्रम बाजार की संरचनात्मक विशेषताएं, कीमत संबंधी आपूर्ति पक्ष के उत्प्रेरक और महंगाई को नियंत्रित करने और रोज़गार पैदा करने के लिए सरकार की पहलें।

(ख) सरकार ने मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में सतत रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के उपायों में मुख्य खाद्य पदार्थों के लिए बफ़र बनाना और समय-समय पर इन पदार्थों को खुले बाज़ार में उतारना; स्टॉक सीमा तय करके और उसमें बदलाव लाकर जमाखोरी को रोकना; भारत ब्रांड के तहत तय खुदरा दुकानों के ज़रिए चावल, गेहूं का आटा, चना, मसूर दाल और मूंग दाल जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को रियायती कीमतों पर वितरित करना और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों में समय-समय पर कमी करना शामिल है। हाल की कुछ पहलों का उद्देश्य देश में दाल और खाद्य तेल के बाज़ारों को सुदृढ़ करना है। ₹42,000 करोड़ के निवेश और ग्रामीण अवसंरचना को आधुनिक बनाने पर केंद्रित 1,100 परियोजनाएं के साथ, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दालों में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किए गए। सरकार ने हाल ही में पीएम-आशा स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश और गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहनों की ₹13,890 करोड़ की खरीद को भी मंज़ूरी दी है। सरकार ने हाल ही में एक संशोधन वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025, अधिसूचित किया है, जो 01 अगस्त, 2025 से लागू है। यह खाद्य तेल के बाज़ार में आपूर्ति-मांग के असंतुलन को ठीक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा, सरकार नौकरी के अवसरों का विस्तार करने और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई- एनयूएलएम), पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं / कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने रोज़गार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा में मदद के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नाम की रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंज़ूरी दी है। इसके अलावा, श्रम और रोज़गार मंत्रालय नेशनल करियर सर्विस (ईसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो करियर से जुड़ी सेवाएं देने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

(ग) मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने और रोज़गार सृजित करने के लिए सरकार के लक्षित पहलों, जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) में रेखांकित किया गया है, ने मुद्रास्फिति कम करने और बेरोज़गारी में कमी लाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद की है। गिरावट का रुझान कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और श्रम बाजार के नतीजों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की निरंतर कोशिशों को दर्शाता है। मैक्रोइकोनॉमिक सुधारों, कौशल विकास संबंधी पहलों और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों ने रोजगार के अवसर सृजित करने और श्रम बाजार को सुदृढ़ करने में मदद की है, साथ ही मुद्रास्फिति के दबाव को कम करने के लिए आपूर्ति-पक्ष से संबंधित व्यवधानों को भी कम किया है।

*****